शिक्षण मंडी

केंद्रीय बोर्ड एवं पियरसन का गठबंधन

कृष्ण कुमार

पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को सेवाओं में बेहतरी के लिए मंत्र के रूप में देखा जा रहा है। जिन क्षेत्रों में राज्य अभी तक कर्ता की भूमिका में था उन्हें भी साझेदारी के नाम पर निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। यह लेख केन्द्रीय बोर्ड एवं पियरसन के बीच हुई साझेदारी के निहितार्थों की जांच-पड़ताल करता है।

केन्द्र सरकार का यह निर्णय वृहत्तर नीति परिदृश्य से मेल खाता है कि पियरसन और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत एक अनुसंधान केंद्र स्थापित करें। लेकिन, इस निर्णय में एक नया मोड़ भी है। एक नीति के रूप में, पिछले कुछ सालों में पीपीपी को इस आग्रह के साथ निरूपित, प्रचारित एवं कार्यान्वित किया गया है कि यह उपाय उन सभी विविध क्षेत्रों के लिए बराबर रूप से कारगर है जिनमें अभी तक मुख्यतः राज्य कर्ता की भूमिका में रहा है। याद पड़ता है कि योजना आयोग का पीपीपी पर एक दस्तावेज मुझे पढ़ने के लिए कहा गया था जो सड़क निर्माण के बारे में था। पढ़ाने वाले को उम्मीद थी कि दस्तावेज को पढ़कर मेरा यह संदेह दूर हो जाएगा कि पीपीपी की नीति पिछड़े ग्रामीण इलाकों में मॉडल स्कूल स्थापित करने में उपयोगी एवं प्रभावशाली सिद्ध नहीं होगी। मुझे तब समझ आया कि पीपीपी को व्यापक रूप से एक वरदान की तरह मान लिया गया है और यह मेरा भ्रम ही था कि यह नीति अभी भी व्याख्या की मोहताज थी।

निजी हितों को बढ़ावा

जाहिर है, मेरे भ्रम की जड़ें, 'साझेदारी' या पार्टनरशिप के उस अर्थ में थीं जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था का पुराना विचार शामिल है। नए नीति परिदृश्य में उस अर्थ के लिए कोई जगह नहीं है। बल्कि वह भ्रामक लगता है। क्योंकि नई नीति का अभिप्राय ही है राज्य के संसाधनों एवं उसकी संरचनाओं का इस तरह से यांत्रिक उपयोग हो जिससे निजी हितों को बढ़ावा मिल सके। जिस 'मिश्रित' विधि की अनुमति नई नीति देती है उसमें निहित मिश्रण का विचार बड़ा विशिष्ट है। मिश्रण के पुराने मॉडल में राज्य के हितों और उसकी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी जाती थी जबकि नई नीति राज्य को सिर्फ एक सहर्ष बढ़ावा देने वाली संस्था की तरह मानती है। ऐतिहासिक नजर से यह कहना सही होगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था निजी पूंजी को उसकी भूमिका अदा करने में बढ़ावा देने के लिए भी थी। अब अंतर यही है कि पीपीपी के तहत राज्य निजी पूंजी को राज्य की क्षमता सुधारने के लिए बढ़ावा दे रहा है और कई मामलों में उसको वे जिम्मेदारियां लेने की तरफ बढ़ा रहा है जो पहले प्राथमिक रूप से राज्य की मानी जाती थीं। राज्य अब उन जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना चाह रहा है।

यह एक परियोजना है कि मूल्य है? यह प्रश्न वैसा ही है जैसा कि उदारीकरण को एक विचारधारा मानें कि एक विकल्प? वास्तव में, "विकल्प" के विचार ने स्वयं उस विचारधारात्मक विस्तार में एक सुरक्षित जगह बना ली है जिस पर नव उदारवादी समाजशास्त्रियों, प्रशासकों एवं राजनीतिज्ञों का दावा रहता है। प्रचलित नीति परिवेश में यह उम्मीद जताई जाती है कि लोग व्यवहारिक आधारों पर ही विकल्प चुनेंगे। इसलिए कई नीतियों के पक्ष में अब यही स्पष्टीकरण दिया जाता है कि उनमें लोगों की चुनाव की क्षमता बढ़ाने या स्वयं विकल्पों को बढ़ाने की संभावना है। अब यह मांग रहती है कि हम लोकतंत्र को ऐसे रखें कि वह सिर्फ विकल्पों का ही संसार है और उसके अलावा शायद उसमें कुछ भी नहीं है। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है कि सरकार भी इस समझ को व्यवहार में ला रही है या उन क्षेत्रों में अपने विकल्प चुनने के अधिकार को स्थापित कर रही है जिनमें कुछ साल पहले तक किसी और को जिम्मा सौंपने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। शैक्षिक मूल्यांकन के लिए अनुसंधान केंद्र का मुद्दा ऐसा ही एक मामला है जिससे राज्य की खुद की विकल्प चुनने की अवधारणा सोदाहरण प्रतिपादित होती है।

पियरसन कंपनी ने केंद्रीय बोर्ड के साथ जो अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है उसका काम बोर्ड को दीर्घकालीन नीतिगत कार्यवाई के लिए सक्षम बनाना है, जैसे कि स्कूल आधारित मूल्यांकन व्यवस्था विकसित करना। इस केंद्र में बोर्ड के सालाना परिणामों का विश्लेषण किया जाएगा जिससे कि बोर्ड को प्रश्नों की किस्म सुधारने में मदद मिले। अच्छे प्रश्न बना पाने की क्षमता परीक्षा व्यवस्था को जांचने की कसौटी में मुख्य निर्धारक होती है क्योंकि उसी से प्रत्याशियों के बीच में वस्तुपरक एवं विश्वस्त रूप से अंतर कर पाने की बोर्ड की भूमिका पूरी होती है। पियरसन की भूमिका आगे चलकर शिक्षकों के प्रशिक्षण में भी होगी जिसके तहत सामग्री तैयार की जाएगी ताकि शिक्षक परीक्षा सुधार एवं मूल्यांकन की नई नीतियों को स्पष्ट रूप से समझ लें खासकर सतत एवं समग्र मूल्यांकन (सीसीई) को। इन प्रस्तावित गतिविधियों की गूढ़ प्रवृत्ति इस तथ्य के मद्देनजर और भी जटिल हो जाती है कि भारत में शिक्षक प्रशिक्षण, नीति एवं प्रणाली दोनों स्तरों पर बहुत ही कमजोर है। अभी हाल के समय तक परीक्षा सुधार को संस्थागत क्षमता की बढ़ोतरी पर निर्भर माना जाता था, खासकर व्यवस्थाई अड़चनें हटाने के लिए शोध आधारित ज्ञान को इस्तेमाल करने की क्षमता पर जोर दिया जाता था। परीक्षा सुधार का काम पीपीपी के रास्ते से एक निजी कंपनी को सौंपना बहुत ही स्पष्ट ढंग राज्य के नजरिए में संस्थागत विकास को लेकर एक तीखा बदलाव दिखाता है विशेषकर अकादमिक क्षमता के मामले में। इस मामले में सरकार ने जो विकल्प चुने हैं वे उतने ही ध्यान देने लायक हैं जितने की वे विकल्प जो चुने नहीं गए।

कृष्ण कुमार
जाने-माने शिक्षाविद्, केन्द्रीय शिक्षण संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं।

सबसे ज्यादा प्रचारित ब्रांड

पियरसन को साझेदार बनाने में केंद्रीय बोर्ड ने स्कूल संबंधी व्यापार जगत के सबसे ज्यादा प्रचारित वैश्विक ब्रांड का चुनाव किया है। शैक्षिक वस्तुओं एवं सेवाओं के वैश्विक बाजार में कहीं भी पहुंच सकने वाले उपभोक्ता की ब्रांड संचेतना पर आधारित किसी भी कसौटी का इस्तेमाल करें, केंद्रीय बोर्ड का पियरसन को चुनने का निर्णय उतना ही विश्लेषण का पात्र है जितना कि उसका राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) का एक साझेदार के रूप में नजरअंदाज करने का निर्णय। आखिरकार, केंद्रीय बोर्ड राष्ट्रीय परिषद् द्वारा बनाया पाठ्यक्रम ही इस्तेमाल करता है... न केवल उसे स्वीकृत रूप से क्रियान्वित करके बल्कि उसे अपने निर्माण की तरह प्रस्तुत करके भी। केंद्रीय बोर्ड इस पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्यपुस्तकों का भी इस्तेमाल करता है, केवल उनको कक्षायी शिक्षण के लिए लागू करके नहीं बल्कि परीक्षा पत्रों को बनाने के एकमात्र आधार की तरह भी। अपने काम में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण आधारित सुधार लाने की योजना के लिए केंद्रीय बोर्ड के पास स्वाभाविक विकल्प राष्ट्रीय परिषद् का था क्योंकि दोनों संस्थाएं एक-दूसरे को लंबे समय से जानती हैं। दोनों की साझेदारी का विचार क्यों अस्वीकृत हुआ होगा? उसके पीछे एक कारण

हो सकता है। वह भी तब जबकि राष्ट्रीय परिषद् के बारे में सोचा गया हो। कि दोनों ही राज्य की संस्थाएं हैं और इसलिए उनसे साथ मिलकर काम करने की उम्मीद तो वैसे भी है ही। पीपीपी नीति का लक्ष्य है निजी साझेदारों की मदद से राज्य की संस्थाओं की दक्षता में सुधार लाना। इस तस्वीर में राष्ट्रीय परिषद् एक साझेदार के रूप में योग्य नहीं ठहरती है। न ही कोई विश्वविद्यालय या सरकारी अनुदान पाने वाला कोई स्वायत्त अनुसंधान संस्थान। राज्य के अपने ढांचे के अंदर सहयोग द्वारा नई संस्थागत क्षमताओं का विकास करना शैक्षिक नीति के लिए प्राथमिकता नहीं है।

पियरसन को साझेदार चुनकर केंद्रीय बोर्ड ने यह भावना जताई है कि उसके लक्ष्य उस दिशा से अलग नहीं हैं जिसमें शैक्षिक नीति को दुनिया के कई हिस्सों में शैक्षिक सेवाओं एवं माल का बाजार ढकेल रहा है। इस बाजार में पियरसन को आजकल अग्रणी 'सीखने या अधिगम' की कंपनी कहा जाता है। जो पाठक शिक्षा के वाणिज्य की नई भाषा से परिचित नहीं हैं उन्हें यह जानना उपयोगी लगेगा कि शैक्षिक व्यापार की शब्दावली में 'सीखने' का मतलब है ज्ञान एवं सेवाओं के पैकेजड रूपों को पाने की इच्छा को स्वीकार करना एवं उसे आत्मसात कर पाना। पैकेजड एवं वस्तु के रूप में ज्ञान को पाने की आदत और कौशल का विकास 'सीखने' के इस नए प्रयोजन में शामिल है। यह विचार कि 'सीखने' के फलस्वरूप ऐसे परिणाम जरूर निकलते हैं जिनको मापा जा सकता है। दोनों तत्कालीन अर्थों में एवं आर्थिक नीति के दीर्घ कालीन लक्ष्यों की नजर से एक और महत्त्वपूर्ण शब्द से जुड़ा हुआ है और वह है 'गुणवत्ता' जो कि नव उदारवादी शैक्षिक विमर्श में समा जाने की खातिर शाब्दिक विकार की प्रक्रिया से गुजरा है। गुणवत्ता का अर्थ अब किसी भी उस प्रयास को मान लिया जाता है जो शिक्षक द्वारा बच्चों के साथ किए जाने वाले काम को बढ़ावा देता है या बाजार के प्रबंधकों की शैली में कहें तो उसमें कुछ मूल्यवान वस्तु या भावना जोड़ता है। पाठ्यपुस्तकों से कुंजियों तक, तकनीकी से सॉफ्टवेयर तक, घरेलू ट्यूशन से कोचिंग तक और फिलहाल भारत के लिए महत्त्वपूर्ण, प्रशिक्षण से परीक्षण तक कई तरह की गतिविधियों से उन उत्पादों और सेवाओं का बाजार बनता है जो सीखने की प्रक्रिया में सुधार ला पाने का दावा करते हैं।

पियरसन इन सभी क्षेत्रों में सक्रिय है और हाल के वर्षों में ऐसे ब्रांड के रूप में उभरा है जो दूसरी ब्रांडों पर जबरदस्त रूप से अपना दबदबा स्थापित कर रहा है। उनमें से कई को पियरसन ने खरीद कर अपने में मिला लिया है। पियरसन द्वारा उपार्जित महत्त्वपूर्ण कंपनियों में से एक है पॉपट्रोपिका जो कि इंटरनेट की सुविधा देने वाली कंपनी है और यह दावा करती है कि आठ लाख बच्चे उसका कहानी नुमा माल खिलौने तस्वीरों वाली किताबें एवं सोशल नेटवर्किंग की सुविधा खरीदते हैं। पियरसन पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशक है। प्रकाशन की दुनिया में स्वायत्त रूप से जाने गए नामों का मालिक है जिनमें इंग्लैंड का एक महत्त्वपूर्ण वित्तीय अखबार शामिल है। पियरसन इंग्लैंड के सात परीक्षा बोर्ड भी चलाता है और भारत में स्कूलों की एक शृंखला स्थापित करने वाला है जो जेम्स टूली के गरीबों की कम लागत वाली शिक्षा के विचार पर आधारित होंगे। अगर केंद्रीय बोर्ड ने राज्य की किसी संस्था या विश्वविद्यालय को वरीयता दी होती तो उसने एक लुप्तप्राय मनोभाव दर्शाया होता और वह भारतीय शिक्षा व्यवस्था की उस छवि से मेल नहीं खाता जिसे निजी विक्रेता एक जानदार और गतिशील बाजार के रूप में प्रचारित करते हैं। यह छवि एक आदर्श समीकरण व्यक्त करती है जिसमें राज्य का जिम्मेदारी से हाथ झाड़ना और संस्थाई अवनति पीपीपी के लिए आधार बन जाते हैं और उसकी जरूरत एक आवेग के साथ महसूस करवाते हैं। केंद्रीय बोर्ड पियरसन अनुसंधान केंद्र को पियरसन से शुरुआती दो वर्षों में पूरा सहयोग मिलेगा। बाद में यह केंद्र स्वावलंबी हो जाएगा। इसका आशय समझ पाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। स्पष्ट है कि स्कूलों को सतत एवं समग्र मूल्यांकन के लिए समर्थ बनाने का लक्ष्य इस तरह साधा जाएगा कि पहले केंद्रीय बोर्ड से संबद्ध स्कूलों को पैकेजड माल इस्तेमाल करने की संस्कृति में ढाला जाएगा और इस प्रक्रिया में परीक्षण एवं शिक्षण के उपकरण शामिल किए जाएंगे। केंद्रीय बोर्ड की पद्धति अपनाने वाले कई स्कूल, जिसमें केंद्रीय सरकार द्वारा चलाए जा रहे विद्यालय शामिल

हैं। शिक्षा को मूल्यवान बनाने में सक्षम कहे जाने वाली सेवाओं का भार मां-बाप पर डाल ही चुके हैं। नौकरी के दौरान प्रशिक्षण समेत शिक्षकों का प्रशिक्षण एक बहुत बड़े उद्योग के रूप में उभर चुका है और अच्छी खासी संख्या में निजी स्कूलों की सेवा कर रहा है। यह सेवा अब राज्य सरकारों के स्कूल तक भी पहुंच रही है, जिसके कारण पीपीपी का विस्तार ऐसे होगा कि राज्यों का धन निजी कंपनियों को देना संभव हो जाएगा। उदाहरण के लिए, हरियाणा ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत होने वाले शिक्षक प्रशिक्षण का काम दो निजी कंपनियों को दे दिया था और हाल में ही अपने राज्य की शैक्षिक परिषद् (एससीईआरटी) को वापस सौंपने का निर्णय लिया है। जाहिर है, हरियाणा सरकार का निजी कंपनियों के साथ कोई बहुत बढ़िया अनुभव नहीं रहा।

शिक्षा के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियां

हरियाणा की कहानी कोई अकेली नहीं है जो कंपनियों द्वारा दी जा रही सेवाओं के प्रति आशावान होने के जोखिम को चित्रित करती है। जोखिम और भी ज्यादा गंभीर हो जाएंगे जब शैक्षणिक काम बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दे दिए जाएंगे। पश्चिमी देशों के बाजारों में वे जैसी सेवाएं देती हैं उससे कहीं भिन्न वे एशिया और अफ्रीका में देंगी। हाल ही में पियरसन भारत के शिक्षक प्रशिक्षण के सूखा ग्रस्त बाजार में एक किताबों की शृंखला लेकर आया है जो बीएड एवं एमएड के विद्यार्थियों के लिए है। 'टीचिंग टैक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट' शीर्षक किताब में लेखक के नाम का कोई चिह्न भी नहीं है तो उसका आकर्षण पूर्णतः प्रकाशक के नाम यानी पियरसन से है। बहुत ही अच्छे से छपी हुई यह किताब उन कुंजियों की तरह ही है जो भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण के बाजार को चित्रित करती हैं। इस बाजार में पियरसन के प्रवेश से यह उम्मीद जगी थी कि आखिरकार आगरा-मेरठ मण्डल में प्रचलित प्रकाशन की दुकानों को प्रतिद्वंद्वी झेलने पड़ेंगे। उसके बदले, पियरसन ने उनकी सामग्री की नकल करने का निर्णय कर लिया और अपनी ब्रांड की शोहरत सिर्फ जिल्द और अच्छे कागज में ही समेट दी।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की उपेक्षा

परीक्षा के व्यापार में संलग्न केंद्रीय बोर्ड की 'गुणवत्ता' सुधारने की तलाश में पियरसन की अनुमानित भूमिका विश्लेषण एवं प्रशिक्षण में होगी। एक बोर्ड के रूप में, केंद्रीय बोर्ड की मुख्य भूमिका विद्यार्थियों का वितरण, पास-फेल और कम-ज्यादा अंकों के मापक्रम पर रखने की है; जिससे विश्वविद्यालय एवं अन्य संस्थाएं अपनी भर्ती की प्रक्रियाएं संपन्न कर पाती हैं। केंद्रीय बोर्ड बहुत भारी संख्या में प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित करता है जिससे सीधे-सीधे डॉक्टरी या इंजीनियरी जैसे प्रोफेशनल कोर्स में विद्यार्थियों का प्रवेश भी नियंत्रित होता है। पियरसन के साथ बोर्ड की साझेदारी का आशय है कि अनुसंधान आधारित पहलू मिलें ताकि इन विविध परीक्षाओं का स्तर और किस्म सुधारने का काम हो सके। सार्वजनिक परीक्षाओं के संदर्भ में गुणवत्ता सुधारने का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है, पूछे गए प्रश्नों की किस्म। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उठाए गए महत्त्वपूर्ण बिंदुओं में से यह एक था। यह बिंदु पाठ्यचर्या के एक दस्तावेज में शामिल किया गया, इसका कारण था कि दसवीं और बारहवीं कक्षा के अंत में होने वाली सार्वजनिक परीक्षाओं का बड़ा भारी असर इस बात पर पड़ता है कि कक्षा में क्या पढ़ाया जाता है और कैसे पढ़ाया जाता है। हालांकि 2005 की पाठ्यचर्या के तहत एनसीईआरटी ने जो नई पाठ्यपुस्तकें तैयार कीं वे ऐसे पढ़ाने के तरीकों की मांग करती हैं जिसमें विद्यार्थियों के लिए समझ बनाना और मुद्दों से जूझना एक लक्ष्य हो, लेकिन परीक्षा व्यवस्था शिक्षक को मजबूर करती रही है कि वह विद्यार्थियों की रटे हुए उत्तर लिख पाने की क्षमता पर ही ध्यान दे। इस दबाव को कम करने के लिए 2005 की पाठ्यचर्या में परीक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन के सुझाव दिए गए थे। पाठ्यचर्या बाल केंद्रित शिक्षण की वकालत इस बात पर बल देते हुए करती है कि मूल्यांकन को बच्चे की जरूरतों पर आधारित शिक्षण का तरीका तय करने का माध्यम मानना चाहिए। इस तर्क के केंद्र

में मूल्यांकन की समूची व्यवस्था है और इसलिए 2005 की पाठ्यचर्या में इस मुद्दे का संबंध शिक्षकों की व्यावसायिक पद्धति और स्वायत्ता से जोड़ा गया है।

इस महत्त्वपूर्ण संबंध को केंद्रीय बोर्ड एवं अन्य बोर्डों द्वारा उठाए गए परीक्षा संबंधी सतही कदमों में बिल्कुल भुला ही दिया गया है। दरअसल, हाल के वर्षों में एक बिल्कुल ही प्रतिकूल हवा चली है जिसमें शिक्षक सीसीटीवी एवं बायोमेटरिक हाजिरी के शिकंजे में आ गए हैं। केंद्रीय बोर्ड की सतत एवं समग्र मूल्यांकन को लागू करने की खुद की पहल एक निर्दयी मशीन की तरह लगती है जो बच्चों और उनके शिक्षकों दोनों को ही हमेशा फंसाए रखने की मंशा महसूस करवाती है। अगर पियरसन इस पहल को सुधार सकता है और इसे मानवीय बना देता है तो यह निश्चय ही एक प्रशंसनीय साहसिक कार्य होगा। अगर वह असफल रहता है तो भारत का राष्ट्र-राज्य इस अनुभव को भी अपनी शिक्षा के दुखदायी रिकॉर्ड में शामिल कर सकेगा। ◆

(इकॉनोमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली से साभार)

भाषान्तर : लतिका गुप्ता